

## कार्यकारी सारांश

राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, (RSTDSP), निवेश परियोजनाओं का चौथा चरण एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित है और राजस्थान अर्बन ट्रिकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा कार्यान्वित है, जिसे पहले राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना (आरयूआईडीपी) के नाम से जाना जाता था। आरएसटीडीएसपी लगभग 14 शहरों में पानी और अपशिष्ट जल सेवाओं में सुधार की दिशा में राजस्थान सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगा। RSTDSP सेक्टर, ऋण के माध्यम से 20,000-115,000 के बीच आबादी वाले माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज (WSS) सेवाओं में सुधार करना चाहता है। परियोजना निम्नलिखित प्रभावों के साथ संरेखित है: (i) राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में पीने योग्य, सस्ती, विश्वसनीय, न्यायसंगत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पेयजल आपूर्ति तक पहुंच में सुधार होगा। (ii) शहरी आबादी, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। राजस्थान के माध्यमिक शहरों में शहरी सेवा वितरण में सुधार होगा।

**2. लक्ष्मणगढ़ शहर जल आपूर्ति उपपरियोजना** आरएसटीडीएसपी के निवेश घटक के तहत डिजाइन की गई उप परियोजनाओं में से एक है। वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ कस्बे में पानी का स्रोत भूजल है। शहर के विभिन्न स्थानों पर 23 नलकूप से शहर को फायदा हुआ है। इसमें से 12 TWA.En हेड वर्क्स पर CWR से जुड़े हैं जबकि 11 TW बड के बालाजी हेड वर्क्स पर सीडब्ल्यूआर से जुड़े हैं। 23 TW को GW स्रोत माना जाता है। 23 नलकूपों से एकत्र किए गए पानी को ए.एन. कार्यालय और बड के बालाजी में साफ पानी के जलाशयों में एकत्र किया जाता है और इसे शहर के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध ईएसआर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वर्तमान में पीएचईडी द्वारा पेयजल आपूर्ति योजना के तहत नगरपालिका सीमा का लगभग 70-80% क्षेत्र शामिल है। शेष क्षेत्र जो नव विकसित है और नगर पालिका क्षेत्र में नए जोड़े गए हैं, पाइप योजना से असंबद्ध हैं। वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ शहर में पानी की आपूर्ति सेवा अविश्वसनीय है, गुणवत्ता के मुद्दों और भारी वितरण नुकसान के साथ युग्मित है।

**3. संभावित प्रभावों की जांच और आकलन-** एडीबी को, बैंक के संचालन के सभी पहलुओं में पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, और पर्यावरण मूल्यांकन की आवश्यकताओं को एडीबी के सुरक्षा नीति वक्तव्य (एसपीएस), 2009 में वर्णित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार, इस उप-परियोजना को ईआईए अध्ययन या पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जल आपूर्ति उप-परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन, एडीबी रैपिड एनवायरनमेंटल असेसमेंट (आरईए) चेकलिस्ट का उपयोग करके किया गया है। पूर्व-निर्माण, निर्माण और संचालन चरणों के संबंध में संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान की गई थी। यह प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) लक्ष्मणगढ़ टाउन, जल आपूर्ति उप-परियोजना के तहत प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के घटकों को संबोधित करती है।

**4.** इस उप-परियोजना का मसौदा आईईई व्यवहार्यता/प्रारंभिक डिजाइन के आधार पर एडीबी द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था, और इस डीबीओ पैकेज की बोली और अनुबंध में शामिल किया गया था। स्कोप, स्थान आदि में किसी भी बदलाव सहित अंतिम उप-परियोजना डिजाइनों को दर्शाने वाला अद्यतन आईईई, और निर्माण शुरू करने से पहले एडीबी द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। चूंकि डिजाइनों को जोन/सबजोन/घटक-वार अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए आईईई को चरणों में अपडेट करने की भी योजना है ताकि उन घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके जिनके लिए डिजाइन तैयार किए गए हैं। यह इस पैकेज का दूसरा अद्यतन आईईई है। पहले अद्यतन IEE को अगस्त 2021 में ADB द्वारा अनुमोदित किया गया था और ADB और RUIDP वेबसाइटों में इसका खुलासा किया गया था। जल नेटवर्क की कुल लंबाई में परिवर्तन और अन्य परियोजना घटकों की स्वीकृति स्थिति में परिवर्तन के कारण इसे अद्यतन (दूसरा अद्यतन) किया जा रहा है। पहले अद्यतन आईईई में; जल आपूर्ति नेटवर्क के तहत प्रस्तावित कुल 162.64 किमी में से 112 किमी (लगभग 68.86%); अनुमोदित किया गया था। वर्तमान में जल आपूर्ति नेटवर्क के तहत, सभी 8 क्षेत्रों में

167.73 किमी (100%) के कुल नेटवर्क को मंजूरी दी गई है और इस प्रकार 5.09 किमी (162.24 किमी की प्रस्तावित लंबाई से 167.73 किमी की अंतिम लंबाई तक) के कुल नेटवर्क की वृद्धि हुई है। नेटवर्क की कुल लंबाई में यह परिवर्तन पुष्टिकरण सर्वेक्षण और परियोजना डिजाइन किए गए नेटवर्क को अंतिम रूप देने के कारण हुआ है। वर्तमान में; सिविल संरचनाओं के तहत, सीडब्ल्यूआर (250 केएल और 100 केएल) दोनों के डिजाइन, क्लोरीनेटर रूम और 1 किलो प्रति घंटे की क्षमता की वैक्यूम फीड क्लोरीनीकरण प्रणाली, पीएचईडी एईएन में 2 सीआरएमसी। परिसर और पीएचईडी Exn परिसर के पास और PHED Exn पर 1 एमसीसी भवन। परिसर को मंजूरी दे दी है। संशोधित और स्वीकृत आईईई, आईईई के पुराने संस्करण का स्थान लेगा और ठेकेदार पर संविदात्मक रूप से बाध्यकारी होगा।

**5. वर्गीकरण** (i) प्रारंभिक विस्तृत डिजाइन, और (ii) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घटकों की सबसे अधिक संभावना के आधार पर लक्ष्मणगढ़ जल आपूर्ति उप-परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मूल्यांकन किया गया है। पर्यावरण मूल्यांकन में पानी की आपूर्ति के लिए एडीबी की आरईए चेकलिस्ट (REA Checklist) और " अशमन परिदृश्य चेकलिस्ट (No Mitigation Scenario Checklist)" का उपयोग किया गया था। लक्ष्मणगढ़ जल आपूर्ति उप-परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना नहीं है जो अपरिवर्तनीय, विविध या अभूतपूर्व हैं। संभावित प्रभाव, ज्यादातर साइट-विशिष्ट होते हैं और उनमें से कुछ अपरिवर्तनीय होते हैं। ज्यादातर मामलों में शमन उपायों को निर्माण स्थलों पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सरल उपायों के साथ डिजाइन किया जा सकता है और जो कि सिविल कार्य ठेकेदारों को पता हो।

**6. लक्ष्मणगढ़ टाउन जलापूर्ति उप-परियोजना को एसपीएस के अनुसार पर्यावरण श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है** क्योंकि कोई महत्वपूर्ण प्रभाव परिकल्पित नहीं है। तदनुसार, यह आईईई पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए शमन और निगरानी उपाय (Mitigation and Monitoring Measures) प्रदान करता है कि परियोजना के परिणामस्वरूप कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

**7. परियोजना का दायरा-** उप-परियोजना को समग्र और एकीकृत तरीके से जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे में अंतराल को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल दक्षता, सुरक्षा में सुधार करना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है; इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस उप-परियोजना के तहत निवेश में शामिल हैं: (i) 19 नलकूपों का पुनर्वास, (ii) बड के बालाजी एचडब्ल्यू पर 250 केएल और पीएचईडी ए.एन. परिसर पर 100 केएल के 2 सीडब्ल्यूआर का निर्माण (iii) वितरण नेटवर्क- 167.73 किमी (75 मिमी से 280 मिमी) (iv) 900 केएल कुल क्षमता के 3 सीडब्ल्यूआर और 3880 केएल कुल क्षमता के 8 ओएचएसआर का पुनर्वास (v) स्काडा प्रणाली के लिए प्रावधान। (vi) 12200 नं हाउस कनेक्शन के लिए प्रावधान (vii) इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य और (viii) 2 सीआरएमसी (पीएचईडी एईएन कैम्पस और पीएचईडी एक्सटेंशन कार्यालय के सामने) और पीएचईडी ईएक्सएन परिसर में 1 एमसीसी का निर्माण।

**11. पर्यावरण का विवरण-** उप-परियोजना घटक सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर और उसके आसपास के इलाकों में स्थित हैं जो कई वर्षों पहले शहरी उपयोग में परिवर्तित हो गए थे, और इन स्थलों पर कोई प्राकृतिक आवास नहीं बचा है। परियोजना स्थल सरकारी भूमि में संरचनाओं के लिए और मौजूदा सड़क के अधिकार (आरओडब्ल्यू) में पाइप बिछाने के लिए स्थित हैं। परियोजना स्थानों में या उसके आस-पास कोई संरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव या मुहाना नहीं हैं। मिट्टी गहरी है, और पाइप बिछाने के लिए चट्टानों को काटने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मणगढ़ शहर की जलवायु गर्म और शुष्क है। ठंड का मौसम नवंबर से फरवरी के अंत तक लगभग साढ़े तीन महीने तक रहता है। अप्रैल से जून के अंत तक की अवधि गर्म मौसम का गठन करती है। मानसून जून के अंत में शुरू होता है। गर्मियों में तापमान 45-50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और सर्दियों में न्यूनतम -2 डिग्री से 4 डिग्री तक गिर जाता है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा (1971-2011) 463.0 मिमी है।

9. **संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय-** बेहतर बुनियादी ढांचे के स्थान, डिजाइन, निर्माण और संचालन के संबंध में संभावित प्रभावों की पहचान की गई। निर्माण चरण के दौरान, मुख्य रूप से अपशिष्ट मिट्टी की मध्यम मात्रा और निवासियों और यातायात की गड़बड़ी के निपटान की आवश्यकता से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में निर्माण के सामान्य अस्थायी प्रभाव हैं, और उनके शमन के लिए अच्छी तरह से विकसित तरीके हैं। सभी नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं।

10. प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया गया जहां परियोजना की वजह से कम से कम प्रभाव हो। (i) भूमि अधिग्रहण और लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता से बचने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर सुविधाओं का पता लगाना; और (ii) भूमि के अधिग्रहण को कम करने और विशेष रूप से शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आजीविका पर प्रभाव को कम करने के लिए मुख्य/पहुंच सड़कों के साथ आरओडब्ल्यू में पाइप बिछाना।

11. कार्यों का उपयुक्त समय निर्धारण (गैर-मानसून मौसम, यातायात दबाव का समय आदि) और सर्वोत्तम निर्माण विधियों द्वारा असुविधा को कम करने जैसे उपायों को नियोजित किया जाएगा जैसे जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां 3.5 मीटर से अधिक की गहराई के लिए और क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए ट्रेचलेस पाइप बिछाने। व्यस्त सड़कों पर पाइप बिछाने के कार्य हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ठेकेदार द्वारा यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जायेगी। परिचालन चरण में, सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा नियमित रखरखाव के साथ संचालित होगा, जिसे पर्यावरण को प्रभावित नहीं करना चाहिए। समय-समय पर सुविधाओं की मरम्मत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन निर्माण अवधि की तुलना में पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम होंगे क्योंकि काम कम होगा और केवल छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।

12. **पर्यावरण प्रबंधन-** इस आईईई के हिस्से के रूप में एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) शामिल है, जिसमें (i) कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों के लिए शमन उपाय शामिल हैं; (ii) एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम, और शमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार संस्थाएं; (iii) सार्वजनिक परामर्श और सूचना प्रकटीकरण; और (iv) एक शिकायत निवारण तंत्र। डिजाइनों में संशोधन करके कई प्रभावों और उनके महत्व को पहले ही कम कर दिया गया है। निर्माण चरण ईएमपी को सिविल कार्य बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

13. सभी नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं। निर्माण के दौरान आयोजित किए जाने वाले पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम द्वारा शमन का आश्वासन दिया जाएगा। पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपायों को लागू किया गया है और यह निर्धारित करेगा कि पर्यावरण को संरक्षित किया गया है या नहीं। इसमें ऑन- और ऑफ-साइट अवलोकन, दस्तावेजों की जांच और श्रमिकों और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार शामिल होंगे। ठेकेदार द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई के लिए किसी भी आवश्यकता के बारे में रुडसिको को सूचित किया जाएगा जो रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं पर सहमति के अनुसार एडीबी को रिपोर्ट करेगा। डिजाइन किए गए उप-परियोजना घटक द्वारा अनुमानित प्रभावों को कम करने के लिए ईएमपी और संबंधित निगरानी उपायों के कार्यान्वयन की लागत लगभग अनुमानित है (बजटीय प्रावधान) लगभग INR 17,587,580 अनुमानित है। (शब्दों में रु. (शब्दों में एक करोड़ पचहत्तर लाख पिचेत्तर हजार पांच सौ अस्सी) है। इस सांकेतिक लागत में एस्बेस्टस प्रबंधन (पहचान, सूची, निष्कासन, परिवहन, अस्थायी भंडारण, निपटान/उपचार, और एस्बेस्टस सामग्री से संबंधित ठेकेदार की समग्र पर्यवेक्षण) के लिए INR 7,000,000 (USD 100,000) शामिल हैं।

14. इस दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मसौदा आईईई और ईएमपी को बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया गया था। ठेकेदार ने समीक्षा और अनुमोदन के लिए पीआईईयू को

एक अद्यतन ईएमपी / साइट-विशिष्ट ईएमपी (एसईएमपी) प्रस्तुत किया है, जिसमें (i) निर्माण कार्य शिविरों, भंडारण क्षेत्रों, सड़कों, बिछाने के क्षेत्रों, ठोस के लिए निपटान क्षेत्रों के लिए डिजाइन किए गए स्थल / स्थान शामिल हैं। और खतरनाक अपशिष्ट; (ii) अनुमोदित ईएमपी के बाद विशिष्ट शमन उपाय; और (iii) प्रति ईएमपी निगरानी कार्यक्रम। एसईएमपी की मंजूरी से पहले किसी भी कार्य को शुरू करने की अनुमति नहीं है। निर्माण अवधि के दौरान ईएमपी/अनुमोदित एसईएमपी की एक प्रति साइट पर रखी गई है।

**15. कार्यान्वयन व्यवस्था-** राजस्थान सरकार का स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) RUDSICO के माध्यम से कार्य कर रहा है, जो परियोजना निष्पादन एजेंसी है। पीएमयू को बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए रुडसिको के डिवीजन में रखा गया है। जयपुर और जोधपुर में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और प्रत्येक परियोजना शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में पीआईयू हैं। पीएमयू एडीबी को पर्यावरण मूल्यांकन और निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी, सुरक्षा उपायों के मुद्दों को संबोधित करने, पीआईयू को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। पीआईयू ईएमपी कार्यान्वयन, सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और अन्य क्षेत्र-स्तरीय गतिविधियों की दिन-प्रतिदिन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। पीएमयू ने पर्यावरण के लिए एक परियोजना अधिकारी नियुक्त किया है और प्रत्येक पीआईयू ने एक सुरक्षा और सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ) की प्रतिनियुक्ति की है। पीएमयू पर्यावरण परियोजना अधिकारी को परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण सलाहकार (पीएमसीबीसी) और निर्माण प्रबंधन और पर्यवेक्षण सलाहकार (सीएमएससी) के विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

**16. परामर्श, प्रकटीकरण और शिकायत निवारण।** हितधारकों को साइट पर चर्चा और शहर स्तर पर एक सार्वजनिक परामर्श कार्यशाला के माध्यम से आईईई विकसित करने में शामिल किया गया था, जिसके बाद व्यक्त किए गए विचारों को आईईई और परियोजना की योजना और विकास में शामिल किया गया था। साइट पर सार्वजनिक परामर्श के अलावा, शहर स्तरीय समिति (सीएलसी) की एक हितधारक बैठक आयोजित की गई और सीएलसी ने उप-परियोजना की सराहना की और उसे मंजूरी दी। IEE को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा, IEE के मसौदे (Draft) और पहले अद्यतन (first updated) किए गए IEE का खुलासा किया गया था, और इस अद्यतन IEE (updated IEE) को ADB और RUDSICO वेबसाइटों के माध्यम से व्यापक दर्शकों के लिए भी प्रकट किया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परामर्श प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और विस्तारित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितधारक परियोजना में पूरी तरह से लगे हुए हैं और इसके विकास और कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए तत्पर हैं। आईईई के भीतर एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का वर्णन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सार्वजनिक शिकायत का त्वरित समाधान किया जा सके।

**17. निगरानी और रिपोर्टिंग-** निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए पीएमयू, पीआईयू और सलाहकार जिम्मेदार होंगे। निर्माण के दौरान, डीबीओ ठेकेदार द्वारा आंतरिक निगरानी के परिणाम पीआईयू को उनकी मासिक ईएमपी कार्यान्वयन रिपोर्ट में दिखाई देंगे। सीएमएससी की सहायता से पीआईयू, ठेकेदार के अनुपालन की निगरानी करेगा, एक त्रैमासिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (क्यूईएमआर) तैयार करेगा और पीएमयू को प्रस्तुत करेगा। पीएमयू कार्यान्वयन और अनुपालन की देखरेख करेगा और एडीबी को अर्ध-वार्षिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (एसईएमआर) प्रस्तुत करेगा। एडीबी पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर डालेगा। निगरानी रिपोर्ट को रुडसिको-ईएपी/पीएमयू वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

**18. निष्कर्ष-** लक्ष्मणगढ़ के नागरिक इसके प्रमुख लाभार्थी होंगे। उप-परियोजना मुख्य रूप से सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के प्रावधान के माध्यम से लक्ष्मणगढ़ शहर की पर्यावरणीय गुणवत्ता और रहने की स्थिति में सुधार के लिए डिजाइन की गई है। इस उप-परियोजना से होने वाले लाभों में शामिल हैं: (i) शहरी गरीबों सहित सभी घरों में उचित दबाव में पीने योग्य पानी की उपलब्धता में वृद्धि; (ii) पानी के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुँचने में कम समय और लागत। (iii) बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेष रूप से जलजनित और संक्रामक रोगों में कमी;

(iv) भूजल संदूषण के जोखिम को कम करना; (v) उपचारित जल आपूर्ति के संदूषण के जोखिम को कम करना; और, (vi) उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के कारण ताजे जल संसाधन पर निर्भरता कम करना, और (vi) उपचारित अपशिष्ट निपटान मानकों को पूरा करने के कारण जल निकायों की गुणवत्ता में सुधार।

19. उप-परियोजना से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़े संभावित प्रभावों को उचित इंजीनियरिंग डिजाइन और अनुशासित शमन उपायों और प्रक्रियाओं के समावेश या आवेदन के माध्यम से बिना कठिनाई के मानक स्तर तक कम किया जा सकता है। दूसरे अद्यतन आईईई के निष्कर्षों के आधार पर, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है और परियोजना "बी" श्रेणी के रूप में जारी है। उप-परियोजना भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना (2006) द्वारा कवर नहीं की गई है।

20. आईईई के दूसरे अपडेट के बाद; परियोजना के सभी घटकों (जल आपूर्ति नेटवर्क, सीडब्ल्यूआर, सीआरएमसी आदि) के डिजाइन को मंजूरी दी गई है और पुनर्वास के लिए प्रस्तावित केवल कुछ घटक जैसे 3 सीडब्ल्यूआर, 8 ओएचएसआर और 19 ट्यूबवेल के पुनर्वास को मंजूरी नहीं दी गई है। शेष घटकों को अनुमोदित और अंतिम रूप दिए जाने पर इस आईईई को फिर से अद्यतन किया जाएगा।

**21. सिफारिशें-** प्रारूप आईईई के निष्कर्षों के आधार पर इस उप-परियोजना के लिए लागू सिफारिश, इस अद्यतन के अनुसार आईईई के मसौदे की सिफारिशों की अनुपालन स्थिति इस प्रकार है;

#### **इस अद्यतन के साथ पहले से लागू अनुशंसाएँ:**

- इस आईईई को बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल करें;- लागू किया गया, एडीबी द्वारा अनुमोदित ड्राफ्ट आईईई बोली दस्तावेजों का हिस्सा है।
- ठेका देने पर ठेकेदार के लिए इंडक्शन करना;- रक्षोपाय इंडक्शन (Safeguard Induction) किया गया।
- सुनिश्चित करें कि ठेकेदार ने काम शुरू करने से पहले योग्य पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) अधिकारियों को नियुक्त किया है;- अनुपालन किया है।
  - प्रथम स्तर के जीआरएम में उपठेकेदारों सहित ठेकेदारों की भागीदारी;- अनुपालन किया गया
- अनुबंध प्रदान करने पर ठेकेदार को सुरक्षा उपायों का संचालन करना-अनुपालन किया गया
- विस्तृत डिजाइन के आधार पर इस आईईई को अपडेट/संशोधित करें और/या यदि कोई अप्रत्याशित प्रभाव, कार्यक्षेत्र, संरेखण, या स्थान में परिवर्तन हो;- IEE को वर्तमान डिजाइन अपडेट के अनुसार अपडेट किया जाता है, आगे इसे अंतिम IEE में अपडेट किया जाएगा।
- यथाशीघ्र सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि शर्तों/प्रावधानों को विस्तृत डिजाइन में शामिल किया गया है;- कोई डब्ल्यूटीपी प्रस्तावित नहीं है इसलिए सीटीई/सीटीओ की जरूरत है।
- ईएमपी कार्यान्वयन का कड़ाई से पर्यवेक्षण करें;- अनुपालन किया जा रहा है
- दस्तावेजीकरण और नियमित आधार पर रिपोर्टिंग जैसा कि आईईई में दर्शाया गया है;- अनुपालन किया जा रहा है
- हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श;- अनुपालन किया जा रहा है
- सूचना का समय पर प्रकटीकरण और जीआरएम की स्थापना;- क्रियान्वित किया जा रहा है
- परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण और लोगों को किसी भी प्रभाव से बचाने के लिए पीएमयू, पीआईयू, परियोजना सलाहकारों और ठेकेदारों की प्रतिबद्धता।- पीएमयू, पीआईयू और सलाहकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

#### **अंतिम आईईई में लागू करने की सिफारिश:**

- साइट-विशिष्ट स्थितियों के अनुसार एस्बेस्टस प्रबंधन योजना को अद्यतन और कार्यान्वित करें;- वर्तमान में उन साइटों पर कोई काम नहीं हो रहा है, जहां एसीएम का सामना किया जा सकता है, एसीएम प्रबंधन योजना को अद्यतन किया जाएगा और अंतिम आईईई में शामिल किया जाएगा।

### सिफारिशें जो इस परियोजना पर लागू नहीं होती हैं

- जैव विविधता मूल्यांकन रिपोर्ट से सिफारिशों को अद्यतन और कार्यान्वित करें:- परियोजना गतिविधियों के कारण जैव विविधता (संकटग्रस्त, संकटग्रस्त या संरक्षित) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस परियोजना के लिए आगे जैव विविधता मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।